

ANUBHUTI-GS1-SEC2

स्व-मूल्यांकन गाइड

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- गठबंधन के उद्देश्यों और उसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
- समझाएँ कि यह पहल किस तरह सतत विकास लक्ष्यों (SDG) 1 और 2 में योगदान देती है।
- मुख्य चुनौतियों की चर्चा करें और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।

2. परिचय में क्या शामिल करें:

- 2024 के G20 सम्मेलन में इस गठबंधन की शुरुआत का संक्षिप्त परिचय दें।
- यह स्पष्ट करें कि यह पहल कोविड के बाद बढ़ती भूख और गरीबी से निपटने के लिए शुरू की गई है।
- इसे वैश्विक विकास प्रयासों जैसे SDGs से जोड़ते हुए भूमिका तय करें।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- संतुलित निष्कर्ष दें — यह स्वीकार करें कि यह गठबंधन ज़रूरी और संभावनाओं से भरा हुआ है।
- दीर्घकालिक सफलता के लिए वैश्विक राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवाचार और समावेशी भागीदारी की ज़रूरत को रेखांकित करें।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

- उद्देश्य: गरीबी कम करना, भूख मिटाना, क्षमता निर्माण करना।
- संरचना: सदस्यता, संस्थागत व्यवस्था, “सिंट्स 2030” जैसे फोकस क्षेत्र।
- महत्व: SDG 1 और 2 के साथ मेल, बहुपक्षीय सहयोग, समावेशी विकास।
- चुनौतियाँ: फंडिंग, भूराजनीतिक अड़चनें, समन्वय की कमी, जलवायु परिवर्तन।
- आगे की राह : फंडिंग उपाय, नीति समन्वय, तकनीकी एकीकरण।

5. महत्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- सतत विकास लक्ष्य 1 और 2
- “सिंट्स 2030”
- जलवायु-सहिष्णु कृषि

- प्रमाण-आधारित नीति
- बहुपक्षीय सहयोग
- खाद्य सुरक्षा
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
- तकनीकी नवाचार
- संरचनात्मक असमानता
- मिलान तंत्र (matchmaking mechanism)

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे मौजूदा कार्यक्रमों से अलग करें।
- भारत की सदस्यता और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करें।
- मौजूदा आँकड़ों का प्रयोग करें (2030 तक अनुमानित भूख/गरीबी स्तर)।
- उदाहरण के तौर पर “स्कूल मील योजना” या “कैश ट्रांसफर योजना” को शामिल करें।
- सामान्य गरीबी/भूख की चर्चा से बचें — केवल गठबंधन केंद्रित उत्तर दें।

ब्राज़ील की G20 प्राथमिकताएँ (2024)

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन में मेज़बान के रूप में ब्राज़ील द्वारा तय की गई मुख्य प्राथमिकताओं को समझाइए।
- ब्राज़ील जिन विषयों और पहलों को आगे बढ़ा रहा है, उनका विश्लेषण करें।
- वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में ब्राज़ील के एजेंडे की प्रासंगिकता को परखें।

2. परिचय में क्या शामिल करें:

- वर्ष 2024 में ब्राज़ील G20 का अध्यक्ष देश बना — शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ।
- ब्राज़ील का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण (Global South) की समस्याओं को प्रमुखता देना और विकास तथा सततता से जुड़े लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- निष्कर्ष में यह दर्शाएँ कि ब्राज़ील वैश्विक शासन व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।
- एजेंडे की सफलता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए **सुनियोजित कार्य योजना, वैश्विक सहयोग, और नज़र रखने वाले तंत्रों** की आवश्यकता को रेखांकित करें।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. ब्राज़ील की तीन प्रमुख प्राथमिकताएँ:

1. भूख, गरीबी और असमानता से लड़ाई:

- “भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन” की शुरुआत।
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 1 और 2 के साथ मेल।

2. ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास:

- स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और न्यायसंगत ऊर्जा बदलाव को बढ़ावा।
- जलवायु वित्त और विकासशील देशों को समर्थन की माँग।

3. वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार:

- संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार की वकालत।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाना (जैसे — सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की माँग)।

B. अन्य विषय और पहल:

- **स्प्रिंट्स 2030 पहल** – SDGs को तेज़ी से लागू करने की कार्रवाई केंद्रित योजना।
- बहुपक्षीय सहयोग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना।
- डिजिटल समावेशन और विकास के लिए बुनियादी ढाँचे का समर्थन।

C. भारत-ब्राज़ील साझेदारी और निरंतरता:

- भारत की 2023 G20 अध्यक्षता द्वारा शुरू किए गए विकास केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ाना।

- IBSA और BRICS जैसे मंचों पर सहयोग को मज़बूती देना ।

5. महत्त्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन
- स्प्रिंट्स 2030
- न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन
- वैश्विक दक्षिण
- बहुपक्षीय सुधार
- ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ
- SDG को तेज़ी से लागू करना
- G20 रियो शिखर सम्मेलन 2024
- जलवायु वित्त पोषण मुहिम
- डिजिटल समावेशन

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- ब्राज़ील की थीम “एक न्यायसंगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण” का उल्लेख करें ।
- ब्राज़ील की दोहरी पहचान को रेखांकित करें — एक उभरती अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय नेता (अमेज़न क्षेत्र) ।
- G20 शेरपा/वित्तीय बैठक के आँकड़े या निष्कर्ष शामिल करें (यदि उपलब्ध हों) ।
- यह दर्शाएँ कि ब्राज़ील का एजेंडा विकास-केंद्रित, समावेशी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को दर्शाने वाला है ।

बिहार में ड्राई पोर्ट

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- शुष्क बंदरगाह/ड्राई पोर्ट क्या होता है – इसकी परिभाषा दें और यह बिहार जैसे स्थलरुद्ध (landlocked) राज्यों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसे समझाएँ।
- बिहार (विशेषकर मधेरा, सारण ज़िले) में प्रस्तावित शुष्क बंदरगाह/ड्राई पोर्ट की स्थिति, उद्देश्य और संभावित लाभ बताइए।
- यह क्षेत्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स ढांचे और बिहार की आर्थिक प्रगति को कैसे प्रभावित करेगा – इसका मूल्यांकन कीजिए।

2. परिचय में क्या लिखें:

- शुष्क बंदरगाह/ड्राई पोर्ट (आंतरिक कंटेनर डिपो) एक ऐसी सुविधा है जहाँ बंदरगाह से दूर बैठकर माल की निकासी और प्रवेश, कस्टम क्लियरेंस, भंडारण और माल ढुलाई होती है।
- बिहार समुद्र से जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ कारगर लॉजिस्टिक्स तंत्र की सख्त ज़रूरत है – ड्राई पोर्ट इसकी भरपाई कर सकता है।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- यह शुष्क बंदरगाह/ड्राई पोर्ट बिहार की औद्योगिक और व्यापारिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है – इसे रेखांकित करें।
- पूरी क्षमता से लाभ लेने के लिए सहायक बुनियादी ढाँचे, नीति समर्थन और व्यापार की सुगमता जैसे सुधारों की आवश्यकता पर बल दें।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. पृष्ठभूमि और स्थान:

- प्रस्तावित ड्राई पोर्ट: मधेरा, सारण ज़िला।
- निर्माण एजेंसी: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA), केंद्र सरकार और कॉनकोर (CONCOR) के सहयोग से।

B. उद्देश्य और विशेषताएँ:

- कस्टम क्लियरेंस, वेयरहाउसिंग, माल की लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा।
- कृषि निर्यात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- रेल नेटवर्क के माध्यम से कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ना।

C. संभावित लाभ:

- कम लागत और समय की बचत – लॉजिस्टिक्स कुशल होगा।
- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी।
- स्थानीय रोज़गार और अधोसंरचना विकास होगा।

D. चुनौतियाँ और ज़रूरी उपाय:

- अंतिम छोर (last-mile) की कनेक्टिविटी – विशेष रूप से सड़क और रेल नेटवर्क की ज़रूरत।
- भूमि अधिग्रहण, विनियामक सहूलियत और आपूर्ति श्रृंखला का विकास।
- लंबे समय तक लगने वाली परियोजना और कई एजेंसियों के बीच समन्वय की ज़रूरत।

E. विकास के व्यापक एजेंडे से संबंध:

- यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है।
- बिहार को पूर्वी भारत में लॉजिस्टिक्स और कृषि-निर्यात हब बना सकता है।

5. महत्त्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- आंतरिक कंटेनर डिपो (Inland Container Depot – ICD)
- मद्रैरा ड्राई पोर्ट
- BIADA
- CONCOR
- लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचा
- व्यापार सुविधा/सुगमता
- निर्यात प्रतिस्पर्धा
- गतिशक्ति योजना

- स्थलरुद्ध अर्थव्यवस्था
- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- आँकड़ों का प्रयोग करें – जैसे बिहार का निर्यात में कम हिस्सा, अनुमानित माल ढुलाई क्षमता।
- कृषि आधारित और हस्तशिल्प उद्योगों को लाभ मिल सकता है – यह दिखाएँ।
- क्षेत्रीय विकास और व्यापार ढाँचे के विकेंद्रीकरण को रेखांकित करें।
- यदि जगह हो तो एक सरल नक्शा या फ्लोचार्ट बनाकर ड्राई पोर्ट की कनेक्टिविटी दिखाएँ।

प्रधानमंत्री सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना (2024)

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- इस योजना के उद्देश्यों, मुख्य विशेषताओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझाइए।
- यह योजना स्वच्छ ऊर्जा बदलाव, बिजली सब्सिडी और घरेलू कल्याण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है – इसका मूल्यांकन करें।
- ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा करें।

2. परिचय में क्या शामिल करें:

- योजना का परिचय दें – यह फरवरी 2024 में शुरू की गई थी, ताकि घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा मिल सके।
- सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, बिजली बिल में कमी, और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को मज़बूती देती है – यह बताएं।
- इसकी सफलता के लिए जन-जागरूकता, समय पर क्रियान्वयन, और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) का सहयोग ज़रूरी है – इस पर बल दें।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. उद्देश्य और लक्ष्य:

- 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना।
- जमीनी स्तर पर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

B. मुख्य विशेषताएँ:

- 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी।
- नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल के ज़रिए आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
- स्थानीय डिस्कॉम के साथ मिलकर स्थापना और बिलिंग का समन्वय।
- बैंक से जुड़ा लोन और नेट मीटरिंग की सुविधा।

C. प्रमुख लाभ और महत्व:

- निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बिजली खर्च का बोझ कम होगा।
- भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य में योगदान।
- सोलर पैनल इंस्टॉलेशन व रखरखाव से स्थानीय रोज़गार के अवसर।
- कोयले पर निर्भरता कम होगी – हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

D. कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- तकनीक को लेकर जागरूकता की कमी और भरोसे की समस्या।
- डिस्कॉम की स्वीकृति में देरी और सब्सिडी के भुगतान में बाधा।
- ग्रिड तैयारियों और ऊर्जा भंडारण के उपायों की ज़रूरत।

E. रणनीतिक दृष्टि और तुलनात्मक पहलू:

- यह योजना पीएम-कुसुम (कृषि हेतु) और भारत के पेरिस समझौते (INDCs) के लक्ष्यों से जुड़ी है।
- शहरी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रयासों को भी मज़बूती देती है।

5. महत्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- रूफटॉप सोलर पावर
- नेट मीटरिंग
- नवीकरणीय ऊर्जा
- विकेंद्रीकृत सौर उत्पादन
- सब्सिडी योजना
- पीएम सूर्य घर योजना
- ऊर्जा परिवर्तन
- जलवायु प्रतिबद्धताएँ
- पावर सेक्टर सुधार
- हरित विकास पहल

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- आँकड़ों का प्रयोग करें – जैसे ₹75,000 करोड़ कुल बजटीय प्रावधान, 1 करोड़ परिवारों को लक्ष्य।
- “LiFE (Lifestyle for Environment)” मिशन से जुड़ाव को रेखांकित करें।
- SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) से संबंध बताएं।
- शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के उदाहरण जोड़ सकते हैं।

BRICS – वैश्विक शासन में भूमिका, विस्तार, भारत के लिए प्रभाव और चुनौतियाँ

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- यह समझाइए कि BRICS वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाने में क्या भूमिका निभा रहा है।
- वर्ष 2023 में हुए BRICS विस्तार का भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा – इसका विश्लेषण करें।

● यह समूह कैसे पश्चिम-प्रधान संस्थाओं (जैसे IMF, विश्व बैंक, NATO, G7) का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कौन-कौन सी अंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं – इन पर चर्चा करें।

2. परिचय में क्या शामिल करें:

- BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) एक ऐसा मंच है जिसकी शुरुआत 2009 में बहुध्रुवीय दुनिया, वित्तीय सुधार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- 2023 में इसके विस्तार में ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया जैसे नए देश शामिल हुए – इससे इसकी महत्वाकांक्षा और दायरा बढ़ा है।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- BRICS भविष्य में पश्चिमी प्रभुत्व का संभावित संतुलन बन सकता है – यह स्वीकार करें।
- लेकिन इसकी विश्वसनीयता, आंतरिक एकता, और वैश्विक प्रासंगिकता पर ही इसका भविष्य निर्भर करेगा।
- भारत को BRICS का उपयोग सुधारों की वकालत करने के लिए करना चाहिए, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित भी रखना होगा।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. वैश्विक शासन में BRICS की भूमिका:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक/New Development Bank (NDB) और कॉन्टिनेजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट/Contingent Reserve Arrangement जैसे संस्थानों का निर्माण — IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में।
- UNSC सुधार, डॉलर पर निर्भरता घटाना, और वैश्विक दक्षिण/Global South को अधिक आवाज़ देने की मांग।
- जलवायु वित्त, डिजिटल संप्रभुता, और व्यापार में निष्पक्षता पर नई सोच को बढ़ावा देना।

B. विस्तार (2023): महत्व और दायरा:

- सऊदी अरब, ईरान, मिस्र जैसे रणनीतिक और तेल-समृद्ध देशों की भागीदारी।
- यह समूह अब केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक विविध और संसाधन-समृद्ध गठबंधन बन रहा है।
- इससे मोल-भाव की ताकत और वैश्विक नीति निर्धारण की क्षमता बढ़ती है।

C. भारत के लिए प्रभाव – अवसर और चिंताएँ:

अवसर:

- ऊर्जा बाजारों तक पहुंच, व्यापार साझेदारी, और डिजिटल/वित्तीय शासन में नई पहल।
- Global South के हितों को एक मंच पर उठाने का अवसर।
- बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार के लिए साझा मंच।

चिंताएँ:

- चीन का दबदबा और प्रभाव और बढ़ सकता है।
- ईरान जैसे देशों की उपस्थिति से भारत के विरोधियों का दबाव।
- BRICS का चीन-नेतृत्व वाला, पश्चिम-विरोधी मंच बनना भारत की **गैर-संरक्षण नीति** को चुनौती दे सकता है।

D. मुख्य चुनौतियाँ जो BRICS को पार करनी होंगी:

- सदस्य देशों के राजनीतिक ढांचे और विदेश नीति में अंतर (जैसे भारत बनाम चीन, ब्राज़ील बनाम रूस)।
- सदस्य देशों के बीच अविश्वास – विशेषकर भारत-चीन तनाव।
- संस्थागत गहराई और नीति कार्यान्वयन की कमी।
- G7 जैसे पश्चिमी समूहों के मुकाबले ठोस परिणाम देने में कठिनाई।
- नए सदस्य देशों की उम्मीदें पूरी करना — जब कोई स्पष्ट चार्टर या सदस्यता मानदंड नहीं हैं।

5. महत्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- वैश्विक दक्षिण/ग्लोबल साउथ
- बहुध्रुवीयता
- डॉलर-मुक्त व्यापार
- BRICS+
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

- रणनीतिक स्वायत्तता
- वैश्विक आर्थिक शासन
- भू-आर्थिक बदलाव
- संस्थागत वैधता
- सहमति-आधारित निर्णय प्रक्रिया

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- NDB द्वारा वित्त पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के उदाहरण दें।
- भारत का QUAD और BRICS के बीच संतुलन बनाने का प्रयास बताएं।
- प्रधानमंत्री मोदी का "समावेशी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था" पर उद्धरण जोड़ें।
- आँकड़े प्रयोग करें — BRICS की वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी: ~40%, GDP में ~25%।
- BRICS और G7 के बीच तुलना तालिका या विस्तार का एक फ्लोचार्ट भी जोड़ सकते हैं।

इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (Indo-Pacific Ocean Initiative – IPOI): महत्व, रणनीतिक जुड़ाव और चुनौतियाँ

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- भारत के समुद्री और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने में IPOI की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा करें।
- यह कैसे मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण से मेल खाता है – यह स्पष्ट करें।
- इस पहल की सफलता के लिए किन संस्थागत और भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है – इस पर चर्चा करें।

2. परिचय में क्या लिखें:

- IPOI का परिचय दें – यह भारत द्वारा 2019 में ईस्ट एशिया समिट में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाना है।
- इसे भारत के SAGAR दृष्टिकोण (क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास) से जोड़ें।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- IPOI भारत की इस मंशा को दर्शाता है कि वह क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता और स्थिरता का आधार बनना चाहता है।
- इसकी प्रभावी सफलता के लिए बहुपक्षीय सहयोग, संस्थागत क्षमताओं, और रणनीतिक निरंतरता की ज़रूरत है – इसे रेखांकित करें।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. भारत के समुद्री और रणनीतिक हितों के लिए महत्व:

- भारत की नौसेना उपस्थिति और प्रभाव को इंडो-पैसिफिक में बढ़ावा देता है।
- ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) और समुद्री डोमेन की जागरूकता को मजबूत करता है।
- हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है।
- आपदा प्रबंधन, व्यापार संपर्क और महासागर संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है।

B. IPOI की संरचना और स्तंभ (Pillars):

- 7 स्तंभ: समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और संपर्क।
- बहु-हितधारक दृष्टिकोण – ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस, इंडोनेशिया जैसे देश अलग-अलग स्तंभों का नेतृत्व करते हैं।

C. नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साथ मेल:

- समुद्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और UNCLOS के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
- ASEAN की केंद्रीयता और QUAD के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
- समुद्री सहयोग के लिए पारदर्शी, समावेशी और गैर-प्रभुत्ववादी ढांचे की वकालत करता है।

D. संस्थागत और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ:

- इंडो-पैसिफिक मंचों में भारत-नेतृत्व वाली पहलों के प्रति चीन का विरोध।
- कोई स्थायी संस्थागत ढांचा या फंडिंग तंत्र नहीं है।

- FOIP, AAGC, ASEAN Outlook जैसे समान कार्यक्रमों की ओवरलैपिंग।
- IORA, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर तालमेल की ज़रूरत।
- भारत के घरेलू संसाधनों की सीमाएँ – नौसेना बजट और एजेंसी समन्वय।

5. महत्त्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- इंडो-पैसिफिक
- SAGAR दृष्टिकोण
- नियम-आधारित व्यवस्था
- UNCLOS
- समुद्री डोमेन जागरूकता
- नेट सुरक्षा प्रदाता
- नीली अर्थव्यवस्था
- बहुपक्षीय सहयोग
- रणनीतिक स्वायत्तता
- ASEAN केंद्रीयता

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- भारत के आधिकारिक वक्तव्य का हवाला दें – IPOI “एक खुली, संधि-रहित क्षेत्रीय सहयोग की पहल” है।
- स्तंभ नेतृत्व के उदाहरण दें – जैसे ऑस्ट्रेलिया समुद्री पारिस्थितिकी का नेतृत्व करता है।
- QUAD, IORA और BIMSTEC के साथ संबंधों का उल्लेख करें।
- भारत की नौसेनिक अभ्यासों जैसे **MILAN** और **मालाबार** का जिक्र करें – इससे रणनीतिक गहराई मिलती है।

23वीं विधि आयोग – उद्देश्य, चुनौतियाँ, प्रभाव और संविधान से मेल

1. प्रश्न की मुख्य माँग:

- 23वीं विधि आयोग के उद्देश्यों और दायित्वों की चर्चा करें।
- इसके सामने आने वाली चुनौतियों और भारत की न्याय व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें।
- यह कैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) और भारतीय समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप है – यह स्पष्ट करें।

2. परिचय में क्या लिखें:

- विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधानिक (non-statutory) निकाय है, जिसका काम कानूनी सुधारों और विधिक संहिताकरण (codification) को बढ़ावा देना है।
- 23वीं विधि आयोग की स्थापना 2023 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में की गई – इसका उद्देश्य नए सिरे से कानूनों की समीक्षा और सुधार करना है।

3. निष्कर्ष में क्या लिखें:

- विधि आयोग एक ऐसे उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में काम कर सकता है जो आधुनिक और समावेशी कानून प्रणाली को आगे बढ़ाए।
- इसकी सिफारिशों को समय पर लागू करना ज़रूरी है ताकि ये संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

4. उत्तर के मुख्य बिंदु (मुख्य भाग में):

A. 23वीं विधि आयोग के प्रमुख उद्देश्य:

- पुराने और अनुपयोगी कानूनों की पुनः समीक्षा और निरसन की सिफारिश।
- कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और आधुनिककरण।
- न्यायिक सुधारों को बढ़ावा देना ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो।
- समकालीन कानूनी विषयों की समीक्षा – जैसे समान नागरिक संहिता (UCC), देशद्रोह कानून, तकनीकी कानून आदि।
- AI, डेटा प्राइवैसी जैसे नए क्षेत्रों में कानूनों की आवश्यकता पर सुझाव।

B. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं – केवल सलाहात्मक होती हैं।

- कई रिपोर्टों को देरी या उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
- कुछ सुधार राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं (जैसे UCC, निजी कानून)।
- मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता।
- संसाधनों की कमी और जन/विधिक जागरूकता का अभाव।

C. भारत की विधिक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव:

- औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति को बढ़ावा।
- न्याय तक पहुँच और प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार।
- पुराने कानून हटाकर कानूनी जटिलता में कमी।
- जन-केन्द्रित शासन और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा।

D. DPSPs और सामाजिक आवश्यकताओं से मेल:

- अनुच्छेद 39A – समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा।
- अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास।
- सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है।
- डिजिटल अधिकार, गीग इकॉनमी, जलवायु न्याय जैसी उभरती आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

5. महत्वपूर्ण कीवर्ड/शब्दावली:

- विधिक सुधार
- पुराने कानूनों का निरसन
- न्यायिक दक्षता
- विधिक संहिताकरण
- न्याय तक पहुँच

- कानूनों का औपनिवेशिक प्रभाव
- अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 44
- समान नागरिक संहिता
- कानूनी आधुनिकीकरण
- संवैधानिक नैतिकता

6. अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु:

- पिछली विधि आयोगों की रिपोर्टों का उल्लेख करें – जैसे मृत्युदंड, चुनावी सुधारों पर रिपोर्ट ।
- आँकड़ों का उपयोग करें – उदाहरण: 2014 से अब तक 1500 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त हुए ।
- उदाहरण दें – जैसे देशद्रोह कानून में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली, या प्रक्रियागत सरलीकरण ।
- विधि आयोग का भूमिका – कानून और समाजिक परिवर्तन के बीच सेतु ।